शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण

*119. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि अधिगृहित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : कर्नाटक सरकार को छोड़कर, किसी भी राज्य सरकार से, जहां नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम, 1976 लागू है, अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित खाली भूमि की मात्रा के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । कर्नाटक सरकार से यह पता चला है कि अधिनियम की धारा 10 (3) के अन्तर्गत बंगलौर नगर संघटीकरण में 13,174·03 वर्ग मीटर रिक्त भूमि को फालतू खाली भूमि के रूप में अर्जन करने के लिये अधिसूचित कर दिया गया है ।

भूमि हीन मजदूर

*120. **श्री कर्पूरी ठाकुर** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने भूमिहीन मजदूर है ?

(ख) गत वर्ष सरकार ने कितने भूमिहीन मजदूरो को भूमि दी थीं ; और

(ग) शेष भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने के लिये सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सूरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की संख्या 456 लाख थी ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) उपलब्ध फालतू तथा अन्य भूमि को पात्र श्रेणियों के व्यक्तियों को (जिन में भूमिहीन कृषि श्रमिक भी शामिल है) वितरित की जाती रहेगी ।

राजस्थान में निर्धन परिवारों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता

966. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वे निर्धन परिवार जिन्हें मकान बनाने के लिये भूमि आवंटित की गई थी, धन की कमी के कारण अपने मकान बनाने की स्थिति में नहीं है !

(ख) राष्ट्रीय बैंकों/जीवन बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इस कार्य के लिये गत तीन वर्षों में अलग अलग कितनी राशि की सहायता दी गई ; और

(ग) इस कार्य की गति को तेज करने के लिये अन्य कौनसी योजनाऐं सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान राज्य सहकारी आवास वित्त समिति लिमिटेड जो कि राज्य स्तर पर एक अपैक्स निकाय है, आवास स्थलों के पात्र

आबंटियों को प्लाटों पर मकानों का निर्माण करने के लिये ऋण सहायता दे रही है। समिति ने अब तक 9.94 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। समिति के लिये वित्त का मुख्य साधन भारतीय जीवन बीमा निगम है।

जून, 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ये मार्गदर्शन जारी किये थे कि वे समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये उद्दिष्ट आवास योजनाओं के लिये वित्तीय व्यवस्था करें। 31 दिसम्बर, 1976 तक राजस्थान के विभिन्न बैंकों ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये उद्दिष्ट आवास योजनाओं के लिये 12.10 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किये थे और दी गई राशि 1.06 लाख रुपये थी।

(ग) ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान सरकार भूमिहीन परिवारों को ईंटे बनाने की मिट्टी बजरी, मुरम, पत्थर आदि जैसी भवन सामग्री बिना मूल्य देती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आवास तथा नगर विकास निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता लेकर राजस्थान आवास बोर्ड के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के प्रश्न पर विचार कर रही है।

ऋण मुक्ति

967. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान ऋण मुक्ति के लिये फर्जी कार्यवाहियों के बारे में सरकार को जानकारी मिली है ;

(ख) क्या सरकार का विचार फर्जी ऋण मुक्ति के ऐसे मामलों की जांच कराने के लिये कोई आयोग या समिति गठित करने का है और यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का भी पता है कि ऋण मुक्ति की आड़ में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ग). कृषि ऋणग्रस्तता से राहत राज्य का विषय है ; राज्य सरकारों ने ऋण स्थगन, ऋणों से मुक्ति तथा ऋणों को कम करने के रूप में ऋण-ग्रस्तता से राहत दिलाने के लिये अधिनियम पारित किए हैं। भारत सरकार का ऋण परिसमापन के लिए की गई झूठी कार्यवाहियों अथवा गंभीर भ्रष्ट तरीकों के मामलों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बड़े नगरों को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए केन्द्र सहायता योजना

968. **श्री कल्याण जैन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व देश के कुछ प्रमुख नगरों को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिये केन्द्र सहायियन योजना प्रारम्भ की गई थी ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन नगरों का कार्य प्रारम्भ किया गया और केन्द्र सरकार द्वारा इस के लिये कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लिये गये अन्य नगरों के नाम क्या हैं ?